†[TRAINS RUNNING AT A LOSS

420. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any scheme has been formulated for the profitable running of those trains which have been running at a loss for a number of years; and

(b) what are the reasons for which the trains referred to above run at a loss?]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामसुभग सिंह) : (क) और (ख) गाड़ियों के लेखे अलग-अलग नहीं रखे जाते और यह बताना संभव नही है कि कौन-कौन गाड़ियां घाटे में चल रही हैं । इस सम्बंध में किसी तरह की योजना बनाने का सवाल नहीं उठता ।

इस बात की निगरानी रखी जाती है कि विभिन्न गाड़ियों में उपलब्ध स्थान का कहां तक इस्तेमाल होता है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार गाड़ियों की व्यवस्था में समंजन किया जाता है ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAM SUBHAG SINGH): (a) and (b) Accounts are not separately maintained for individual trains and it is not possible to say which trains have been running at a loss. The question of formulating any scheme in this connection does not arise.

The occupation of different trains is kept under observation and adjustments are made from time to time, in the train services.]

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के मजदूरों की मांगें

४२१. **श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :**
श्री गिरिराज किशोर कपूर :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन कारणों से सरकार ने हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में काम करने वाले मजदूरो की हड़ताल को अवैध घोषित किया है ;

(ख) मजदूरों की प्रमुख मांगें क्या है ; और

(ग) मजदूरो और प्रशासन के बीच अच्छे सम्बध स्थापित कराने के लिये क्या प्रयत्न किये गये है ?

†[DEMANDS OF WORKERS IN THE HEAVY ELECTRICALS LTD.

421. SHRI V. M. CHORDIA:
SHRI G. K. KAPOOR:

Will the Minister of INDUSTRY AND SUPPLY be pleased to state:

(a) the reasons for which Government declared the strike by the workers of the Heavy Electricals Ltd., Bhopal as illegal;

(b) what are the major demands of the workers; and

(c) what attempts have been made to establish cordial relations between the workers and the administration?]

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरी के मंत्री (श्री टी० एन० सिंह) : (क) हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड के मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल को सरकार ने गैर-कानूनी नही घोषित किया । लेकिन प्रबन्धकों की प्रार्थना पर श्रम-न्यायालय भोपाल के न्यायाधीश ने हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० के कर्मचारियों द्वारा २१ मार्च १९६४ और २८ मार्च, १९६४ को प्रारम्भ की गई हड़ताल को मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्बंध अधिनियम की धारा ८०

†[ ] English translation.

के विरुद्ध होने के कारण गैर-कानूनी घोषित किया था ।

(ख) हड़ताल के शुरू होने से पहले हैवी इलैक्ट्रिकल्स कर्मचारी व्यापार सघ द्वारा, जिसे मान्यता प्राप्त नही है, निम्नलिखित मागें रखी गई थी —

(१) कर्मचारियों को भोपाल क्षेत्र के वर्तमान जीवन-यापन खर्च के अभिसूचक अंक के अनुसार मंहगाई भत्ता दिया जाए जिसका निर्धारण शत प्रतिशत बराबर करने के सिद्धात के अनुरूप हो । जब तक इस प्रश्न पर निर्णय किया जाए, सभी कर्मचारियो को ३० रूपए प्रतिमास की अतिरिक्त रकम तदर्थ रूप मे दी जाए ।

(२) १९६२–६३ के वित्तीय वर्ष से सभी कर्मचारियो को एक मास के वेतन के बराबर वार्षिक बोनस दिया जाए ।

(३) औद्योगिक और अनऔद्योगिक कर्मचारियो के बीच छुट्टियो के लिए बर्ते जाने वाले फर्क को दूर किया जाए ।

(४) किसी भी कर्मचारी का वेतन १०० रुपये प्रतिमास से कम नही होना चाहिए और दैनिक आधार पर वेतन पाने वाले और सामयिक रूप से काम करने वाले कर्मचारियो को कम से कम एक वर्ष तक कारखाने मे कार्य करने के बाद नियमित कर्मचारियो मे शुमार किया जाए । किसी भी कर्मचारी की मासिक आय १२० रुपये प्रतिमास से कम न हो । जैसा कि हिन्दुस्तान एन्टिबायटिक्स लि०, पिपरी के मामले मे औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अपने फैसले मे स्पष्ट किया था ।

(५) कार्यालय का काम करने वाले कर्मचारियों के कार्य के घन्टे अधिक से अधिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो के कार्य-घन्टो के बराबर ही होने चाहिये और अतिरिक्त घन्टो के लिए उन्हे ओवर टाइम भत्ता मिलना चाहिए ।

(६) कारीगरो और अन्य समान प्रकार के कर्मचारियों का वेतन-मान जो बहुत कम है, परिवर्द्धित किया जाए । निम्न श्रेणी के क्लर्कों की मासिक आय कम से कम १७० रुपये प्रतिमास होनी चाहिए, जैसा कि हिन्दुस्तान एन्टिबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के मामले मे औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अपने फैसले मे निर्देश दिया है ।

(७) कर्मचारियो पर आश्रित उनके परिवार के सभी सदस्यो को मुफ्त स्वास्थ्य-सेवा और बीमारों को मुफ्त खाने की सहूलियतें होनी चाहियें ।

(८) प्रबन्धको द्वारा अपनाए जाने वाली उन्नति और कर्मचारी सम्बधी नीतियो मे तुरन्त सुधार होना चाहिए ।

(९) वह आदेश, जिसके द्वारा कर्मचारियों को विभागीय दड दिया जाता है, वापिस लेना चाहिए ।

(१०) प्रस्तावित प्रोत्साहन परियोजना से प्रभावित होने वाले कारखाने के अधिकांश कर्मचारियो द्वारा उसके स्वीकृत होने पर उसे लागू किया जाये ।

(११) श्रम-सम्बध तुरन्त ही केन्द्रीय श्रम कानूनो के अन्तर्गत लाए जाये जो पूर्ण-रूपेण भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहे ।

(१२) हैवी इलैक्ट्रिकल्स कर्मचारी यूनियन को प्रदान की गई मान्यता समाप्त की जाए और कर्मचारियो मे गुप्त प्रणाली के द्वारा मतदान जानने के बाद अधिक मत प्राप्त करने वाले कर्मचारी सघ को मान्यता प्रदान की जाए ।

(१३) निदेशक मडल मे कर्मचारियो का कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिए ।

(ग) कर्मचारियों के प्रतिनिधि संघों के मामलों की जिम्मेदारी प्रबन्धकों पर है जो आपसी समझौते के आधार पर उनकी तकलीफों को दूर करते हैं ।

†[THE MINISTER OF HEAVY ENGINEERING IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND SUPPLY (SHRI T. N. SINGH): (a) The Government did not declare the strike by the workers of Heavy Electricals (India) Limited, as illegal. But on an application filed by the management, the Presiding Officer, Labour Court, Bhopal, declared the strike (commenced by the employees of Heavy Electricals (India) Limited, on the 21st March, 1964 and 28th March, 1964) as illegal as it was in contravention of Section 80 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act.

(b) The demands put forward by the Heavy Electricals Servants Trade Union, an unrecognised Union, before the commencement of the strike were as under:—

(i) The dearness allowance of the employees should be linked with the cost of living index of Bhopal region with cent-percent neutralisation formula. Pending a decision on this question, an *ad hoc* increase of Rs. 30.00 p.m. should be given to all employees.

(ii) A minimum annual bonus of one month's pay should be given to all employees from the financial year 1962-63.

(iii) Discrimination of leave facilities between industrial and non-industrial workers should be removed.

(iv) The minimum basic pay for any employee should not be less than Rs. 100.00 p.m. and all the work-charged, daily rated and casual labourers in the industry should be promoted to the regular cadre at least immediately after the completion of one year's service in the organisation. The total wage earnings of any employee should not be less than Rs. 120.00 p.m. as awarded by the industrial tribunal in the case of Hindustan Antibiotics, Limited, Pimpri.

(v) The working hours of the ministerial staff should be reduced to correspond with the working hours of the Central Government employees or they should be given extra allowance for extra hours worked.

(vi) The present pay scales of artisan and other categories which are low at present, should be revised. The total wage earnings of a lower division clerk should be raised to at least Rs. 170.00 p.m. as awarded by the Industrial Tribunal in the case of Hindustan Antibiotics, Pimpri.

(vii) There should be free medical treatment for all dependents of the employees and free diet facilities for all the patients.

(viii) There should be a radical change in the present promotion and personnel policy of the management.

(ix) The order inflicting departmental punishment on certain employees should be withdrawn.

(x) The proposed incentive scheme should be implemented after the same is ratified by the majority of the affected workers of the factory.

(xi) The labour relations should immediately be brought under the Central Labour Laws and within the sole jurisdiction of the Government of India.

(xii) The recognition granted to Heavy Electricals Employees Union should be withdrawn and recognition should be granted to the Union which enjoys the confidence of the majority of workers by ascertaining their wishes through secret direct ballot; and

†[ ] English translation.

(xiii) The Board of Directors should have at least one representative from amongst the employees.

(c) The management deals with the representative Union of the workers and sorts out the grievances on a mutually acceptable basis.]

EXPANSION OF DURGAPUR, BHILAI AND ROURKELA STEEL PLANTS

422. SHRI M. P. BHARGAVA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is proposed to expand the steel plants at Durgapur, Bhilai and Rourkela;

(b) if so, what are the expansion plans and when are they likely to come into operation; and

(c) whether the three plants have been working to their full capacity during the first eight months of 1964?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI N. SANJIVA REDDY): (a) and (b) Yes, Sir. During the Third Five Year Plan period Bhilai is being expanded to 2·5 million tonnes ingot capacity, Durgapur to 1·6 million tonnes and Rourkela to 1·8 million tonnes These expansion plans are likely to be completed during 1966-67 in the case of Rourkela and Durgapur and a little earlier in Bhilai.

(c) During the first eight months of the year, Bhilai Steel Plant has been working above the rated capacity and Durgapur Steel Plan very near the rated capacity. Rourkela Steel Plant has, however, worked to about 79 per cent of steel ingot capacity and 77 % of saleable steel capacity. This was due to one of the blast furnaces being under re-lining and the civil disturbances earlier this year which seriously affected the working of this particular plant.

बिना टिकट चलने वाले मुसाफिर

४२३. श्री राम सहाय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से अगस्त, १९६४ तक प्रत्येक रेलवे पर बिना टिकट सफर करने वाले कितने मुसाफिर पकड़े गये और उनसे कितना धन बतौर किराया और जुर्माना के वसूल किया गया ?

†[TICKETLESS PASSENGERS

423. SHRI RAM SAHAI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the number of ticketless passengers arrested on each railway during the period from January to August, 1964 and the amount of money realised from them as fare and penalty?]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम सुभग सिंह) : एक बयान साथ नत्थी है जिसमे जनवरी से जुलाई, १९६४ तक की सूचना दी गयी है । (देखिए परिशिष्ट ४९ अनुपत्र संख्या ३०) अगस्त, १९६४ की सूचना अभी उपलब्ध नही है ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAM SUBHAG SINGH): A statement giving the information for the period from January to July, 1964 is attached. (*See* Appendix XLIX, Annexure No. 30).

Information relating to the month of August, 1964 is not yet available].

SALE OF COMMON SALT AS FERTILIZER

424. SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Will the Minister of INDUSTRY AND SUPPLY be pleased to state:

(a) the names of States where action has been initiated against organised sale of common salt as fertilizer; and

(b) the nature of the action taken against such sales?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND SUPPLY (SHRI BIBUDHENDRA MISRA): (a) No instance has so far come to notice

†[ ] English translation.